विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

आईआईएससी, जेएनयू और बीएचयू क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर चार साल से बनी हुई हैं। उल्लेखनीय प्रदर्शन जामिया मिलिया इस्लामिया का कहा जा सकता है, जिसने उथल–पुथल और विवादों के बीच भी देश की टॉप टेन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में अपना नाम शुमार करवा लिया।

रमेश शर्मा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से हर साल जारी की जाने वाली एनआईआरएफ रैंकिंग में विश्वविद्यालयों की चोटी की जगहें इस साल भी पिछले कुछ वर्षों जैसी ही रहीं। आईआईएससी (बेंगलुरु), जेएनयू और बीएचयू क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर चार साल से बनी हुई हैं। उल्लेखनीय प्रदर्शन जामिया मिलिया इस्लामिया का कहा जा सकता है, जिसने उथल–पुथल और विवादों के बीच भी देश की टॉप टेन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में अपना नाम शुमार करवा लिया। इससे पहले तीन साल से यह लगातार 12वें स्थान पर बनी हुई थी।

बहरहाल, एनआईआरएफ रैंकिंग में प्रतिष्ठित स्थान पाने वाले ये विश्वविद्यालय ग्लोबल रैंकिंग में ज्यादा ऊंची जगह नहीं ले पाते। इसी हफ्ते घोषित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देश का कोई भी विश्वविद्यालय पहले सौ विश्वविद्यालयों में नहीं गिना गया। दोनों सूचियों पर एक साथ गौर करें तो कुछ और दिलचस्प बातें उभर कर सामने आती हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग की ओवरऑल कैटिगरी में पहला स्थान पाने वाला आईआईटी मद्रास क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग में 275 वें स्थान पर है जबकि देश में आईआईटी दिल्ली से भी नीचे आने वाला आईआईटी बॉम्बे ग्लोबल लिस्ट में 172वें नंबर पर है। इस उलझी हुई गुत्थी का हल उन अलग–अलग पैमानों में है जो इन दोनों सूचियों को तैयार करते समय अपनाए जाते हैं।

एनआईआरएफ रैंकिंग तय करने के लिए टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, रिसर्च, इन्क्लूसिविटी, प्रफेशनल प्रैक्टिसेज और परसेप्शन जैसे कारक देखे जाते हैं जबकि क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग तय करते समय ऐकडेमिक रेप्युटेशन, एम्प्लॉयर रेप्युटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेश्यो, इंटरनैशनल फैकल्टी, इंटरनैशनल स्टूडेंट और पर–फैकल्टी साइटेशन (यानी हर शिक्षक को कितनी जगह उद्धृत किया गया) जैसे पहलुओं पर नजर रखी जाती है। इनमें रेप्युटेशन जैसे फैक्टर तय करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि अगर भारतीय संस्थान बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती करके टीचर–स्टूडेंट रेश्यो सुधारने की कोशिश करें तो वे पर–फैकल्टी साइटेशन के मोर्चे पर कमजोर हो जाते हैं क्योंकि इन नए टीचर्स को शोधपत्रों में रातोंरात तो उद्धृत किया नहीं जाने लगेगा। इसमें लंबा वक्त लगेगा और तब तक वे इस मोर्चे पर कमजोर ही रहेंगे।

यह एक बड़ी वजह है कि भारतीय संस्थान ग्लोबल रैंकिंग में लगातार नीचे ही बने हुए हैं। शायद इन कारकों की अव्यावहारिकता के चलते ही भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री ग्लोबल रैंकिंग को खारिज करते हुए अपना लक्ष्य एनआईआरएफ रैंकिंग को ही वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करना बताते हैं। यह स्वयं में एक प्रशंसनीय लक्ष्य है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए चिंता की बात यह होनी चाहिए कि हमारे शिक्षा संस्थान ग्लोबल रैंकिंग में पिछले वर्षों के मुकाबले भी नीचे क्यों लुढ़कते जा रहे हैं।

अपना संतुलन

अशोक वोहरा। अपने मादक पदार्थ का मजा लेते हुए, अपने विचारों के बारे में जागरूक रहें यदि आप 'अपरिभाषित क्षेत्र' के विस्तार को महसूस करते हैं, तो आपको अपनी वाणी और कार्यों के बारे में अधिक सचेत और ध्यान देने की जरूरत है। जब आप को लगे कि आप भ्रान्ति से घिर रहे हैं तब पीना बंद कर दें। नशीले पदार्थों के स्तरों को स्थिर होने के लिए समय दें। जब आप किसी सामाजिक जगह पर हों तो जागरूकता को अपनाएं। कई बार लोग अधिक शराब पी लेते हैं और अन्य लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। कभी–कभी परिस्थिति सच में बदसूरत बन सकती है, आक्रामक भी। कई बार, वह व्यक्ति जिसने पिछली शाम अनुचित व्यवहार किया था, अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करता है।

संपादकीय

वर्चस्व का नमूना

आशा की किरण सिर्फ एक है कि भारत के विशाल बाजार को ध्यान में रखते हुए या विश्व राजनय में अपने अलगाव को देखते हुए चीनी नेतृत्व गलवान घाटी के टकराव को चर्चा से बाहर रख रहा है। इस बीच कुछ चीनी सैनिकों के हताहत होने की बात भी सुनाई पड़ी है, लेकिन चीनी मीडिया में यह सिरे से गायब है। बुधवार को प्रकाशित 'पीपल्स डेली' और 'ग्लोबल टाइम्स' में इस टकराव की कोई खबर तक नहीं है। चीनी विदेशमंत्री का कहना है कि उनका देश इस मामले को ज्यादा हवा नहीं देना चाहता। लेकिन, उनका बयान सार्थक तब होता, जब पहले नहीं तो कम से कम इस जानलेवा टकराव के बाद चीनी फौज गलवान घाटी और फिंगर फोर से अपना कब्जा हटा लेती। ऐसा हुआ होता तो बातचीत की कुछ जगह भी खुली रहती। लेकिन नियंत्रण रेखा के स्थायी उल्लंघन के बाद खुद को शांतिप्रिय बताना वर्चस्व का एक नमूना भर है, जिस पर गौर करना भी भारत के लिए जरूरी नहीं है। उस समय तंग की कही बात संसार के कुछ इतिहास सिद्ध कथनों में गिनी जाती है– 'हमारी पीढ़ी ने कोशिश करके देख लिया, पर आपस के झगड़े हम नहीं सुलझा पाए। ऐसे में सीमा विवाद सुलझाने का काम क्यों न हम अगली पीढ़ियों पर छोड़ दें, जो निश्चय ही हमसे ज्यादा समझदार होंगी। इसके बजाय हम अपना ध्यान व्यापार पर केंद्रित करें, जिसके लायक क्षमता हमारे पास है और जिसे हम लंबे समय तक करते रह सकते हैं।' चीनी नेतृत्व की मौजूदा पीढ़ी शायद तंग श्याओ फिंग से बहुत आगे जा चुकी है, इसीलिए अपने ज्यादातर पड़ोसियों से उसके टकराव के रिश्ते हैं और जमीन तो छोड़िए, समुद्र तक में फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनेई और किन–किन देशों से उसका सीमा विवाद देखने को मिल रहा है।

रही बात सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे किसी जवाबी कदम की तो ठीक–ठीक पाकिस्तान की तरह चीन के खिलाफ इसकी आजमाइश की सलाह शायद ही कोई रणनीतिकार दे।

फिर सर्जिकल स्ट्राइक?

चंद्रभूषण।

सोमवार की रात भारत और चीन के फौजियों में टकराव भले ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सिर्फ एक बिंदु पर हुआ हो, लेकिन इसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि एशिया के इन दोनों महादेशों के आपसी रिश्तों का समूचा व्याकरण ध्वस्त हो गया है। बुधवार, 17 जून की दोपहर मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी वर्चुअल बैठक का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथियारों के बिना हुई इस लड़ाई में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को मौन श्रद्धांजलि के साथ किया और इससे पहले कहा कि वे मारते–मारते मरे हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी इस बात का एक अर्थ यह लगाया जा सकता है कि जैसे पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक आतंकी ठिकाने पर बमबारी की थी, वैसा ही कुछ निकट भविष्य में चीन के खिलाफ भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह इस कार्रवाई का नतीजा भारत–पाक युद्ध के रूप में सामने नहीं आया, उसी तरह शायद चीन के खिलाफ भारत की सीमित सैन्य कार्रवाई भी जंग के मुकाम तक न पहुंचे।

दूसरे छोर से देखने पर प्रधानमंत्री की बात का एक शांतिपूर्ण अर्थ भी हो सकता है। यह कि

चीन को लंबी अवधि में अपनी इस हरकत का नुकसान उठाना पड़ेगा, और हमारे जवानों ने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए कुर्बानी दी है, लिहाजा सीमावर्ती क्षेत्रों में इसी काम के लिए बनाई जा रही सड़क, पुल और बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर में इस प्रकरण से कोई व्यवधान नहीं पड़ने दिया जाएगा। रही बात सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे किसी जवाबी कदम की तो ठीक–ठीक पाकिस्तान की तरह चीन के खिलाफ इसकी आजमाइश की सलाह शायद ही कोई रणनीतिकार दे। एक मायने में गलवान घाटी की टकराहट उड़ी या पुलवामा के आतंकी हमलों से बुनियादी तौर पर भिन्न भी रही है।

यह कोई चोरी–छिपे किया गया हमला नहीं बल्कि सीधे दो फौजी टुकड़ियों की धक्कामुक्की थी, लिहाजा इसका प्रतिकार भी चीनी फौज, यूं कहें कि चीन के खिलाफ माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसे युद्ध शुरू करने की कार्रवाई समझा जाएगा, जिसके लिए न तो अभी का समय उपयुक्त है, न मुद्दा पर्याप्त है।

अलबत्ता प्रधानमंत्री के इस संक्षिप्त वक्तव्य से एक बात स्पष्ट है कि लद्दाख का मौजूदा टकराव अब दोनों तरफ के फौजी कमांडरों के बूते की बात नहीं रह गया है, और राजनयिकों की वार्ता से भी इसका कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। यह सही है कि दोनों देशों के रिश्ते 1962 या 1988 से बहुत आगे आ चुके हैं। 6 लाख करोड़ रुपये का कारोबार, भारी–भरकम निवेश और लाखों नौकरियां इनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बनी हुई जिस समझ ने इन रिश्तों का तंबू तान रखा था, जब वही एक झटके में छिन्न–भिन्न हो गई तो सिर्फ हितों और स्वार्थों के आधार पर इन्हें कितनी दूर तक खींचा जा सकेगा? इनके संभलने की एक क्षीण सी संभावना राजनीतिक स्तर पर ही है, लेकिन भारत की तरफ से ऐसी कोई पहल अभी अटपटी लगेगी और चीन ऐसा कुछ करके दुनिया भर के अपने बहत्तर और उलझावों में नरमी का संकेत नहीं देना चाहेगा। 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते 12 साल के लिए बिल्कुल खत्म हो गए थे।

अष्टयोग-5087

1			4	3		2
5	33	7	35		28	
		2		6		5
	32	3	38		32	
7	5			4	2	1
	33	1	31		30	4
3			6		5	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5086 का हल

4	3	7	5	6	1	2
5	33	3	35	1	27	7
6	1	4	7	2	5	3
3	26	2	40	7	34	6
1	3	6	7	5	2	4
2	29	1	33	4	30	5
7	4	5	2	3	6	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

वापस शून्य हो जाने का खतरा

मोहन। अगले ही साल सिक्किम सीमा पर घात लगाकर किए गए एक हमले में भारत के चार सैनिकों की शहादत से इनके वापस शून्य हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। 1978 में रिश्ते सुधारने की उम्मीद में भारतीय विदेशमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन के लिए रवाना हुए, पर वे रास्ते में थे तभी चीनी फौजें भारत के एक मित्र देश वियतनाम की सीमा में घुस गईं और वाजपेयी ने पेइचिंग हवाई अड्डे से ही अपनी यात्रा रद्द करके वापस लौटने का फैसला किया। दोनों देशों के आपसी रिश्तों का मौजूदा व्याकरण दिसंबर 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और चीन के कम्यूनिस्ट सुप्रीमो तंग श्याओ फिंग की ऐतिहासिक बातचीत में रचा गया, जिसका सारतत्व सीमा विवाद को परे रखकर व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने का था। लिखित समझौते सिर्फ वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को लेकर हुए, पर खाका ऐसा बदला कि अबतक चल रहा है।